भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1254

(जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

पूर्वोदय योजना की स्थिति

1254. **श्री दिनेश चंद्र यादव:**

श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार देश के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं, के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त योजना के तहत आने वाले सभी राज्यों को प्रदान की जा रही सहायता का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक एक योजना (स्कीम नहीं) तैयार करने की घोषणा की, ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन बनाने हेतु मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों के सृजन को कवर किया जा सके। इस दिशा में, नीति आयोग ने पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी सलाहकार समिति का गठन किया था। तदनुसार, केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत तीन प्रमुख पहलों; (i) दुर्गापुर में एक नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास; (ii) पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का निर्माण और (iii) 4,000 ई-बसों के प्रावधान की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने पूर्वोदय की घोषणा के बाद से पिछले केंद्रीय बजट में पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए अनेक अन्य पहल की हैं, जैसे कि गया में एक औद्योगिक नोड का विकास; सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास, नामत: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर; और बिजली परियोजनाएं, जिनमें पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करना शामिल है। अतिरिक्त उपायों में ओडिशा में पर्यटन स्थलों के विकास; विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारे (वीसीआईसी) के तहत आंध्र प्रदेश में कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र; पोलावरम सिंचाई परियोजना; हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे (एचबीआईसी) के तहत आंध्र प्रदेश में ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय सहायता; रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान; खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण आदि को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारों की स्थापना हेतु ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित खनिज समृद्ध राज्यों के लिए सहायता शामिल है।

****